कार्यकारिणी सारांश

प्रारूप

पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव निर्धारण प्रबंधन योजना

खूंटी जलापूर्ति योजना

नवंबर 2017

झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (जुडको)

झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (जेएमडीपी)

कार्यकारिणी सारांश

परिचय

झारखंड सरकार ने नगर विकास और आवास विभाग (यूडीएचडी) को चयनित शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में शहरी सेवा वितरण और शहरी प्रबंधन क्षमता में सुधार के उद्देश्य से झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (जेएमडीपी) तैयार किया है। जेएमडीपी झारखंड के जिलों में कई उप परियोजनाओं की योजना तैयार करने और उनके क्रियान्वयन पर जोर देता है। झारखंड सरकार ने झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवपलमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको लिमिटेड) की पहचान की है जो कि जेएमडीपी को निष्पादित करने के लिए प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी है। झारखंड सरकार जेएमडीपी की लागत के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांग रही है।

जुडको द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ एक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क (ईएसएमएफ) तैयार किया गया है: कार्यान्वयन और प्रोजेक्ट चक्र के दौरान संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का आकलन और प्रबंधन करने के लिए; निवेश की सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए; और राष्ट्रीय पर्यावरण और सामाजिक कानून और विश्व बैंक की सुरक्षा नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए,

जैसा कि ईएसएमएफ के लिए आवश्यक है, खूंटी जलापूर्ति उप–परियोजना के लिए स्क्रीनिंग, वर्गीकरण, पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) और प्रबंधन योजना, डीपीआर सलाहकारों से स्वतंत्र एक सलाहकार द्वारा बैंक के आवश्यकताओं के अनुसार ओपी 4.01 श्रेणी ए परियोजना तैयार की गई है,। प्रभावों की पहचान करने और उपयुक्त शमन उपाय को सुझाने के लिए जल और स्वच्छता के लिए डब्लूबीजी ईएचएस दिशानिर्देश, और उधोग क्षेत्र के दिशानिर्देशों का इस्तेमाल किया गया है।

खूंटी जलापूर्ति उप–परियोजना के बारे में

खूंटी नगर पंचायत में खूंटी जलापूर्ति योजना, जेएमडीपी के तहत कार्यान्वयन के लिए उप–परियोजनाओं में से एक है और यह दस्तावेज इस उप–परियोजना की ईएसआईए और इ.एस.एम.पी है। वर्तमान जलापूर्ति योजना में 0.9 एमएलडी पानी की आपूर्ति होती है जो कि आंशिक रूप से 30 प्रतिशत शहरी क्षेत्र को आच्छादित करती है। यह पहली बार 1982 में एक 3 एम.एल.डी, वितरण नेटवर्क, एक इंटेक के साथ, और एक ESR के साथ बनाया गया था। बाद में इंटेक वेल और डब्ल्यूटीपी की पंपिंग सुविधा को वर्ष 2006 में अपग्रेड किया गया था, जिसके बाद नियमित पाइप जलापूर्ति प्रणाली को कमीशन किया गया था। प्रस्तावित उप–परियोजना मौजूदा प्रणाली को विस्तार करके, 13.54 एमएलडी पानी क्षमता तक अंतिम डिजाइन वर्ष 2048 तक के लिए बढ़ाएगा।

तजना नदी पर मौजूदा इंटेक वेल, परियोजना के लिए पानी का स्रोत बन जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार ने विभाग द्वारा स्वयं जाँच कर और डीपीआर के भाग के रूप में तैयार जल संतुलन गणना के आधार पर, इंटेक की क्षमता में वृद्वि की गई पानी की निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है। इंटेक और प्रस्तावित नई डब्ल्यूटीपी को जोड़ने वाली वर्तमान प्राकृतिक जल की मुख्य पाइपलाइन को 500 मिमि व्यास और 1650 मीटर लंबाई के पाइपलाइन के साथ बदला जाएगा। मौजूदा डब्लयूटीपी को सेवामुक्त कर दिया जाएगा और एक नई 16 एमएलडी क्षमता का डब्ल्यूटीपी विकसित किया जाएगा और 4 ईएसआर (3 नए और 1 नवीनीकृत) एवं 8.7 कि.मी. नयी राइजिंग मेन के साथ जोड़ा जाएगा और 100 प्रतिशत घरेलू (8350) कनेक्शन की अपूर्ति के लिए इस परियोजना के तहत 122 किलोमीटर की नई वितरण लाइनें स्वचालित मीटर के साथ लगाई जाएगी। पूरी परियोजना को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, वितरण में लगे पुराने पीवीसी, एचडीपीई और सीआई पाइपों की जगह नए डीआई पाइप लगाये जायेंगे। परियोजना के कार्यान्वयन के 5 वर्षो बाद तक संचालन और रखरखाव के लिए सहायता प्रदान किया जाएगा।

लागू पर्यावरण और सामाजिक नीतियां

खूंटी जलापूर्ति परियोजना के लिए लागू प्रमुख पर्यावरण और सामाजिक कानून जल (निवारण और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974 है; जल (निवारण और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 2012; वायु (निवारण और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1981, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006; निर्माण और तोडे. गए अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, ध्वनी प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 देश के श्रम कानून और सड़क विक्रेताओं के (जीवन रक्षा और स्थिर वेंडिंग का नियमन) अधिनियम, 2014।

इसके अलावा, विश्व बैंक द्वारा निर्धारित परिचालनातमक नीतियों का एक संग्रह भी परियोजना पर लागू होगा, जो ओपी 4.01 पर्यावरण मूल्यांकन; ओपी 4.36 वन; ओपी 4.12 अनैच्छिक पूनर्वास; ओपी 4.10 स्वदेशी लोग; और सूचना और प्रकटीकरण तक पहुँच पर विश्व बैंक नीति। यह परियोजना डब्ल्यूबीजी ईएचएस दिशानिर्देशों, और जल और स्वच्छता पर डब्ल्यूबीजी उधोग क्षेत्र के दिशानिर्देशों का भी पालन करेगी।

सार्वजनिक और हितधारक परामर्श

पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन के एक भाग के रूप में, जनवरी 2017 में प्रोजेक्ट डिजाइन और ईएसआईए के विकास में जानकारी लेने और अक्टूबर 2017 में ईएसआईए के एक उन्नत ड्राफ्ट पर खूंटी में सार्वजजिक/हितधारको के साथ परामर्श के दो दौर आयोजित किए गए थे। इसके अलावा उप–परियोजना से संबंधित जानकारी, कार्य अनुसूची, शामिल प्रक्रियाएँ, परियोजना के घटकों को अंतिम रूप देने के साथ प्रभावों की पहचान, हकदार लोग, शमन उपाय और शिकायत निवारण तंत्र पर चर्चा की गई और प्रसारित किया गया। सार्वजनिक रूप से हितधारक, यूएलबी, भू–राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), जल संसाधन विभाग आदि भी परामर्श में शामिल थे। परामर्श से उत्पन्न होने वाले सुझाव डिजाइन और समाधान योजनाओं में उचित रूप में शामिल किए गए है।

ईएसआईए के तैयार करने के लिए सार्वजनिक परामर्श में आए सुझाओं का सारांश नीचे विस्तृत है:

(i) इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है या संरचनाओं पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ii) प्रभाव गैर–स्वामित्व धारकों तक सीमित हैं। परियोजना के कारण केवल 2 गैर– स्वामित्व धारक की संरचना प्रभावित होगी। वास्तविक निर्माण प्रक्रिया के दौरान अनुमानित 20 दिनों के लिए 35 पीएपी की आय की अस्थायी रूप से नुकसान होगा। प्रभावित होने वालों मे केवल एक अनुसूचित जनजाति का परिवार है।

(iii) अस्थायी प्रभावों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। एंटाइटेलमेंट मैट्रिक्स के प्रासंगिक प्रावधान को जनता को बताया जाएगा और उसी के एक हिंदी संस्करण को संवेदक के आने से पहले लोगों के बीच वितरित किया जाएगा। स्थानीय लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में भी सूचित किया गया है।

(iv) निर्माण चरण के दौरान उत्पन्न होने वाले ध्वनि और वायु प्रदूषण के मुद्दे को लोगों ने उठाया है और उपयुक्त शमन उपायों के कार्यान्वयन के लिए अनुरोध किया है।

(v) किसी भी संभावित प्रदूषण से बचने के लिए पानी की पाईपलाइनों को सड़क के किनारे बने वर्षा–जल निकासी नालों से अलग रखना चाहिए।

(vi) सार्वजनिक उपयोग के लिए निःशुल्क पानी के नल पर विचार किया जाना चाहिए।

(vii) जैसा कि लोगों द्वारा सूचित किया गया है, संवेदक को परियोजना में स्थानीय लोगों (मुख्य रूप से महिला) के रोजगार के लिए प्रावधान रखना चाहिए।

स्क्रीनिंग, वर्गीकरण और प्रभावों का आकलन

उप–परियोजना की जाँच परिशिष्ट– । में संलग्न चेकलिस्ट के अनुरूप किया गया था। खूंटी शहरी जलापूर्ति परियोजना को पर्यावरण के तहत ई–1 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ईएसएमएफ मार्गदर्शन के अनुसार, संवेदनशील पर्यावरण क्षेत्रों में शामिल सभी परियोजनाएं, जिनमें वन क्षेत्र शामिल है, E-1 वर्गीकरण के योग्य होंगे। प्रस्तावित उप–परियोजना में संरक्षित वन क्षेत्र में 233 मीटर की पाइप लाइन की प्रतिस्थापना शामिल होगी।

उप–परियोजना के कारण महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित है (क) जल की गुणवता और मात्रा में सुधार; (ख) स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि; (ग) भू: जल के उपयोग में कमी (घ) परियोजना क्षेत्र के भीतर रहने वाले लोगों के जीवन स्तर और स्वच्छता में सुधार; ओर (ई) जलापूर्ति के बुनियादी ढ़ाचों की स्थिरता का प्रबंधन करने के लिए यूएलबी की बेहतर संस्थागत क्षमता।

यह ईएसआईए उप–परियोजना के सभी चरणों ; डिजाइन, निर्माण और संचालन के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों की पहचान करता है। उप–प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन पुरानी जल आपूर्ति योजना के संरेखण पर लागू किया जाएगा क्योंकि उप–प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित सभी अवसंरचना के अवयव शहर और उसके आस–पास स्थित है। निर्माण चरण के दौरान अपेक्षित पर्यावरणीय

प्रभावों में शामिल हैः (क) पुरानी जलापूर्ति योजना (पुरानी डब्ल्यूटीपी, और ईएसआर, और पुराने वितरन लाइनों के निपटान के लिए) से कचरा और निर्माण मलबे का उचित निपटारा कि व्यवस्था करता है। (ख) उत्खनन गतिविधियां, जिससे मिट्टी की क्षरण, वनस्पति और दुर्घटना और चोट के जोखिम बढ़ते है। (ग) धूल, वायु, ध्वनि प्रदूषण और शहर के यातायात/ पैदल यात्री के आवागमन (खासकर जहां पाईपलाइनें प्रमुख सड़कों को पार करती है) में बाधाएं बढ़ जाती है। यह प्रभाव साइट विशिष्ट होगा, और ज्यादातर मामलों में मामूली शमन उपायों से ठीक किया जा सकता है। यूएलबी ने एक लैंडफिल साइट का पहचान किया है जिसकी क्षमता मलबे और कचरे के निष्पादन लिए उपयुक्त है, इसके अतिरिक्त संवेदक मजदूर शिविर की स्थापना के लिए मौजूद WTP के निकट एक साइट जो की 1 एकड़ से अधिक है पहचान किया गया है, जहां 50–60 प्रवासी श्रमिकों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। यह परियोजना किसी भी भौतिक सांस्कृतिक संसाधन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करती है, और खूंटी शहर में कोई ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्वपूर्ण स्थान नहीं है।

परियोजना के लिए कोई भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। तीनों इएसआर और इंटेक के लिए भूमि पहले से ही नगर निकाय के कब्जे में है। करीब 1650 मीटर की पाइपलाइन का उन्नयन किया जाएगा और 130.758 किलोमीटर की नयी बिछायी जाएगी, नवनिर्धारित पाइप आर.ओ.डब्लू के भीतर होगा और भूमि के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होगा। इस परियोजना में सड़क के आर.ओ.डब्लू में दो गैर–स्वामित्व धारकों के दो ढांचों को नुकसान पहुंचना शामिल है। पाइप बिछाने के समय भी 35 सड़क विक्रेताओं के लिए अस्थायी रूप से आय का नुकसान होने की संभावना है। ईएसएमएफ वर्गीकरण मानदंडो के अनुसार, खूंटी जलापूर्ति परियोजना को एस–2 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक अलग एआरएपी देश के कानूनों की आवश्यकता और विश्व बैंक के संचालन नीति 4.12 को अनैच्छिक पुनर्वास को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है।

300 मिमी की मौजूदा प्राकृतिक पानी की पाइपलाइन को 500 मिमी पाइपलाइन द्वारा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होगी। 233 मीटर की प्राकृतिक पानी की पाइपलाइन की मौजूदा संरेखण वन भूमि पर स्थित है (जिसके लिए 0.02 हे0 क्षेत्र का उपयोग किया जाएगा) भी अनुसूचित-V क्षेत्र में है। इसके लिए एक अनापत्ति पत्र, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) के तहत प्रमण्डलीय वन अधिकारी, खुंटी द्वारा प्रदान किया गया है। चूँकि यह कानूनी रूप से नामित, संरक्षित वन है, ईएसएमपी अनापत्ति प्रमाण पत्र में दी गई सभी सिफारिशों का पालन करेगी, वन के किसी भी पेड़ को काटा नहीं जाएगा और लागू अधिनियम के तहत् प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

के अनुसार पारंपरिक वनवासी समुदाय से ग्राम सभा में सहमति ली गई है। एक अनुसूचित जनजाति भागीदारी योजना (एसटीपीपी) भी तैयार की गई है ताकि सभी उप–परियोजना चक्र में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विश्व बैंक की नीति 4.10 को स्थानीय लोगों और ओ.पी. 4.36 वनों पर पूरा किया जा सके। ईएसएमपी संवेदनशील क्षेत्रों को नुकसान/परेशान करने और किसी भी प्रभाव से बचने के लिए सभी एहतियाती उपायों को भी निर्दिष्ट करता है। लिए

ऑपरेशन चरण के प्रभाव बहुत ही न्युन है, ईएसआईए ने ऑपरेशन चरण के दौरान डब्ल्युटीपी ऑपरेटर के व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम के लिए प्रभावी तंत्र और समाधान रखा है और ऑपरेशन चरण के दौरान डब्ल्यूटीपी से निकलने वाले गाद का पर्याप्त उपचार के बाद ही निपटान किया जाएगा। चूँकि गाद से पानी को पुनः प्राप्त किया जाता है और डब्ल्यूटीपी में पुनः परिचालित किया जाता है, इसलिए जल उपचार प्रक्रिया से कोई अपशिष्ट जल उत्पन्न नहीं कया जाएगा। खुंटी नगर पंचायत (केएनपी) क्षेत्र के लिए एक सीवरेज व्यवस्था की योजना बनाई जा रही है, और यह अगले 4–5 वर्षो में पूरी तरह चालू हो जाएगी।

पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना

एक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना (इएसएमपी), जिसमे चिन्हित शमन उपायों पर विस्तार से बताया गया है, और उनके कार्यान्वयन के साधन, निगरानी योजना और शामिल लागत ESIA के साथ तैयार किए गए है। निर्माण चरण के लिए 29.22 लाख और ओएंडएम चरण में 5 साल के लिए 25.4 लाख रूपये का प्रावधान।

ईएसएच प्रशिक्षण, शमन, अपशिष्ट निपटान और श्रम शिविर की लागत परियोजना लागत में शामिल की गई है। पर्यावरण गुणवत्ता की निगरानी एवं, श्रम के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किया गया है। प्रबंधन योजना रख–रखाव चरण को भी सम्मिलित करता है साथ ही साथ यह पानी कि गुणवत्ता की निगरानी एवं गाद प्रबंधन विशेष रूप से जोर दिया जाता है।

संक्षिप्त रीसेटमेंट एक्शन प्लान (एआरएपी) ने 7.74 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित किया है। हालांकि, अनुसूचित जनजाति भागीदारी योजना (एसटीपीपी) के तहत अलग बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। क्योंकि वन निवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन की व्यवस्था ईएसएमपी और एआरएपी के समान है। यह समग्र उप–परियोजना लागतों में शामिल किया गया है।

शिकायत निवारण तंत्र

राज्य और शहरी स्थानीयन निकाय स्तर पर जीआरसी की स्थापना की जाएगी। इसका उददेश्य प्रभावित समुदायें की परियोजनाओं के पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं के बारे में चिंताओं, पूछताछ, .फरियादों और शिकायतों को प्राप्त करना और उन्हें हल करना है जो कार्यान्वयन के दौरान सामने आ सकते हैं, साथ ही साथ उप–परियोजना के कार्यान्वयन होने पर सामाजिक समन्वय और एकीकरण से संबंधित अन्य सामाजिक मुद्दों को संबोधित करना है। जुडको के जीआरएम पर सूचना संचार के कुछ साधनों में निम्नलिखित रूप शामिल है:

- सार्वजनिक स्थानों के लिए पत्रक का वितरण
- सूचना पट्ट
- जुडको की वेबसाइट
- दूरसंचार उपकरण

उप परियोजना निदेशक (जुडको, पीएमयू) प्रत्येक उप–परियोजना की गतिविधियों से संबंधित सभी शिकायतों को संभालने के लिए एक प्रभावी बहु स्तरीय जीआरएम का स्थापित्व सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे है। जीआरएम 2 स्तरों पर कार्य करेगाः समुदाय स्तर पर जहाँ मुद्दों को हल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा; और उप–परियोजना स्तर पर जहाँ एक जीआरसी की स्थापना की जाएगी जो राज्य स्तर पर अपीलीय तंत्र के रूप में होगा। उप–परियोजना स्तर के जीआरसी निम्नलिखित व्यक्तियों के साथ गठित किया जाएगा।

- शहरी स्थानीय निकाय/ कार्यान्वयन एजेंसी से
- कोई निर्वाचित प्रतिनिधि (स्थानीय परियोजना क्षेत्र; प्राथमिकतः महिला)
- महिला समख्या/महिला मंडल जैसे महिलाओं के एक समुदाय आधारित समूह का प्रतिनिधि
- एक व्यक्ति जो सार्वजनिक रूप से जाना जाता है और स्थानीय लोगों द्वारा (परियोजना क्षेत्र में) उनकी ओर से बोलने के लिए (यूएलबी के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा पहचाने जाने के लिए)
- पीआईयू से सामुदायिक विकास अधिकारी
- चिकित्सा अधिकारी

- संबंधित विभाग जैसे पुलिस, परिवहन और श्रम के अधिकारी
- यूएलबी - स्तर समुदाय आयोजक या मुख्य नागरीय पदाधिकारी के प्रतिनिधि

पीएपी को शिकायत के क्षेत्र को स्पष्ट करना होगा। जीआरसी रख–रखाव अवधि के दौरान आजीविका या संपत्ति/यूटिलिटी के नुकसान या पहुंच पर प्रतिबंध, श्रमिक समुदाय के विवाद, निर्माण स्थल का प्रबंधन और सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली निर्माण गतिविधियों से संबंधित शिकायतों पर विचार करेगा। भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को केवल झारखंड के भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के तहत निपटाया जाएगा।

पीएपी (या उसका प्रतिनिधि) अपनी शिकायत जीआरसी को किसी भी लिखित पत्र, फोन या ईमेल द्वारा दर्ज करा सकते है या वैकल्पिक रूप से परियोजना कर्मचारियों के साथ किसी सार्वजनिक या व्यक्तिगत बैठक में अपनी आवाज उठा सकते है। एक बहुत ही सरल शिकायत फार्म स्थानीय भाषा में प्रत्येक परियोजना स्थल पर शिकायतकर्ता द्वारा भरने के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा यूएलबी कार्यालय, पीआईयू कार्यालय और संवेदक शिविर/कार्यालय में शिकायत बक्से रखे जाएँगे। पीआईयू और संवेदक कार्यालय, खूंटी में एक व्यक्ति को सभी शिकायतों (मौखिक या लिखित) को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार शिकायत पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा जो इस तरह की शिकायतों और कार्रवाईयों को अभिलेखित करेगा। शिकायत अधिकारी अशिक्षित शिकायतकर्ताओं के मामले में शिकायत फार्म को भरने में सहायता करेगा। एआरएपी कार्यान्वयन के लिए लगे गैर–सरकारी संगठन, सभी शिकायतों/सुझावों, विशेषकर पीएपी और स्थानीय समुदाय के, पीआईयू प्रमुखों के संज्ञान में रहे यह सुनिश्चित करने में सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करेगा। जीआरएम की प्रभावशीलता, निर्माण पर्यवेक्षण और गुणवत्ता परामर्शदाताओं (सीएसक्यूसी) और एआरएपी कार्यान्वयन के लिए एनजीओ की प्रगति प्रतिवेदन द्वारा पता लगाया जाएगा।

राज्य स्तर पर पंजीकृत शिकायतों/सुझावों के संपर्क विवरण नीचे दिए गए है:

शिकायत निवारण कोषांग
झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
तीसरा मंजिल, प्रगति सदन, कचहरी चौक
राँची– 834001, झारखंड
फोन नं0: 0651 2243203
ईमेलः grc.jmdp.juidco@gmail.com

आम तौर पर शिकायत की प्राप्ति से 7–10 कार्य दिवसों के भीतर जीआरसी समुदाय स्तर पर मामले को सुलझाने और हल करने के लिए मिलेंगे और सिफारिश करेंगे। यदि 10 दिनों के बाद भी कोई निर्णय नहीं होता है, तो पीएपी या कोई अन्य पीड़ित व्यक्ति शिकायत को उप परियोजना निदेशक (जुडको, विश्व बैंक

पीएमयू) को भेज सकता है। डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर (जुडको, वर्ल्ड बैंक पीएमयू) एक अपीलीय समिति की अध्यक्षता करेंगे, जो 20 दिनों के भीतर शिकायत की जाँच कर बताएँगे। यह माना जाता है कि कुछ शिकायतों को उनकी जटिलता के कारण हल करने में अधिक समय लग सकता है, उदाहरण के लिए, भूमि विवाद से संबंधित। ऐसे मामलों में, पीड़ित पक्ष को 20 दिनों के भीतर कारणों और अग्रीम कार्रवाई के साथ देरी की संभावना को सूचित किया जाएगा, सभी प्रस्तुत शिकायतों को उप–परियोजना स्तर पर पंजीकृत किया जाएगा और जुडको–जेएमडीपी पीआईयू के डेटाबेस में जोड़ा जाएगा, जिस पर जुडको–जेएमडीपी के नामित कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से निगरानी रखी जाएगी। ऊपर बताये गए तंत्र के अलावा, पीएपी को देश की न्यायपालिका के पास जाने का अधिकार है।

लैंगिक मुद्दे, कार्य योजना और अनुश्रवण संकेतक

परियोजना में मुख्य लैंगिक मुद्दे, शहरी बुनियादी सुविधओं और सेवाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, महिला कार्यबलों की भागीदारी में असमानता और महिलाओं में उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता में असमानता है।

यह परियोजना बेहतर सड़कों एवं 24x7 घरेलू पानी की आपूर्ति के माध्यम से घरों को बेहतर शहरी बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित करेगी। सड़कों पर उचित प्रकाश व्यवस्था से महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। संवेदक द्वारा स्थानीय लोगों को काम पर रखा जाएगा, प्राथमिकतः महिलाएँ। कार्यान्वयन परामर्शदाता/गैर सरकारी संगठन महिलाओं के बीच परियोजना से उपलब्ध उनके अधिकारों और अवसरों के संबधं में जागरूकता में वृद्धि करेगा।

उप–परियोजना क्षेत्र में विशेषतः महिला प्रधान परिवारों में कमजोर आबादी के लिए जलापूर्ति कनेक्शन कि संख्या ही निगरानी संकेतक है, संवेदक की प्रगति प्रतिवेदन में कार्यरत महिलाओं कि संख्या, उनकी मजदूरी एवं शिकायत निवारण तंत्र/प्रणाली कि मासिक स्थिति शामिल है।

ईएसएमपी पर्यवेक्षण के लिए संस्थागत और कार्यान्वयन व्यवस्था

जुडको में राँची स्थित राज्य पीएमयू , पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपयों को संबोधित करने के लिए समग्र रूप से जिम्मेदार होगा। एक पर्यावरण और सामाजिक विशेषज्ञ पीएमयू में पहले से ही कार्यरत हैं। पीएमयू खूंटी में स्थित परियोजना कार्यान्वयन यूनिट (पीआईयू) द्वारा समर्थित होगा, जो ईएसएमपी, एआरएपी ओर एसटीपीपी के दिन–प्रतिदिन के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। पीएमयू विशेषज्ञ पीआईयू और अन्य कार्यान्वयन संस्थाओं में विशेषज्ञों को प्रशिक्षित एवं उनकी क्षमताओं को मजबूत करेंगे।

यह परियोजना एआरएपी के क्रियान्वयन के लिए योग्य असैनिक सोसायटी संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों को खूंटी जलापूर्ति परियोजना के तहत अन्य सामाजिक गतिशीलता/अईईसी गतिविधियों की नियुक्ति करेगी।

निर्माण पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण परामर्शदाता (CSQC) कि नियुक्ति भी प्रक्रिया में है और इसमें ई.एस. एम.पी, श्रम प्रबंधन व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं और कचरा प्रबंध प्रक्रियाओं के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए एक समर्पित पर्यावरण, सामाजिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिकारी शामिल किये जायेंगे।

परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) पीएमयू और पीआईयू को सामाजिक एवं पर्यावरण विशेषज्ञों का अतिरिक्त समर्थन प्रदान करेगी ताकि खुंटी जल आपूर्ति परियोजना के सभी संबंधित सुरक्षा उपायों का अनुश्रवण करेगा।

ESMP, श्रम प्रबंधन एवं OHS प्रबंधन का अनुपालन संवेदक द्वारा किया जाएगा तथा निर्माण के दौरान अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य PIU एवं CSQC परामर्शी द्वारा किया जाएगा तथा PMU कर्मी द्वारा इसका औपचारिक निरिक्षण किया जाएगा। कार्यो का एक सुरक्षन अकेंक्षण भी कराया जाएगा जिसे स्वतंत्र परामर्शी द्वारा सम्पादित किया जाएगा।